

किसानों का 2 लाख तक कृषि कर्ज माफ

सरकार का 50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार का लक्ष्य, महाराष्ट्र बजट 2026-27 : 2 लाख तक कृषि ऋण माफी

► हरित ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और महिला उद्यमिता पर जोर

मुंबई, 06 मार्च. महाराष्ट्र विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत दिवंगत उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार को श्रद्धांजलि देकर की।

राज्य में फसल ऋण का बकाया रखने वाले पात्र किसानों को 2 लाख रुपये तक की ऋण माफी दी जाएगी। इसके साथ ही नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन भी मिलेगा।

राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और वैश्विक बाजारों तक पहुंच के लिए 10 से 15 प्रमुख फसलों की कृषि मूल्य श्रृंखला मजबूत करने की योजना बनाई है। बजट में सिंचाई और जल क्षेत्र के सुधार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई पहलों का भी विस्तार किया



गया। सरकार ने स्टार्टअप और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं की रूपरेखा पेश की। महाराष्ट्र के हरित ऊर्जा रोडमैप के तहत 2029 तक 50 प्रतिशत और 2035 तक 65 प्रतिशत हरित ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

बजट के अनुसार, पात्र किसानों को फसल ऋण का बकाया रखने पर 2 लाख रुपये तक की माफी मिलेगी, जबकि नियमित ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए 50,000 रुपये

राज्यपाल जिष्णु रह चुके हैं त्रिपुरा के पूर्व उपमुख्यमंत्री

महाराष्ट्र के नवनियुक्त राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल हैं और त्रिपुरा के पूर्व उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं। श्री वर्मा जल्द ही राज्यपाल के रूप में पद की शपथ लेंगे। वह श्री आचार्य देवव्रत का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2025 से महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। त्रिपुरा के अगरतला में 15 अगस्त, 1957 को जन्मे श्री वर्मा राज्य के पूर्व शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वह महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के भतीजे और प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देव बर्मा के चाचा हैं। उनके पिता रमेश किशोर देबबर्मा ने महाराजा के सैन्य सचिव और गृह सचिव के रूप में कार्य किया था। श्री वर्मा ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बीए (ऑनर्स) की पढ़ाई पूरी की है।

कुल बजट अनुमान 7.69 लाख करोड़ रुपए रखा गया

कुल बजट अनुमान 7.69 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 6.16 लाख करोड़ और राजस्व व्यय 6.56 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं। फडणवीस ने कहा, सरकार का लक्ष्य राज्य में 1200 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क और 6000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे विकसित करने का है।

1. सिंचाई और जल आपूर्ति के क्षेत्र में बजट में कई नदी-जोड़ परियोजनाओं और जल उपलब्धता सुधार योजनाओं का उल्लेख है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को क्रमशः 55 और 135

लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

2. स्वास्थ्य क्षेत्र में नागपुर में महाराष्ट्र जन स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का विस्तार और 4,500 करोड़ रुपये की ग्रामीण रोग पहचान परियोजना की घोषणा की गई। 3. हरित ऊर्जा के क्षेत्र में 2029 तक 50 प्रतिशत और 2035 तक 65 प्रतिशत लक्ष्य के साथ बड़े वृक्षारोपण अभियान और रूफटॉप सोलर पहल की भी घोषणा की गई। 4. औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए

18 मेगा औद्योगिक केंद्र और प्रत्येक जिले में एमएसएमई केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। 5. हर जिले में सूक्ष्म और लघु उद्योग केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। सरकार ने कहा है कि इससे 50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। 6. बजट में मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। वडला से गेटवे ऑफ इंडिया तक नई भूमिगत मेट्रो लाइन का उल्लेख है। 2029 तक मुंबई में 165 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क तैयार होगा।

फांसीघर को टिफिन रूम बताना शहीदों का अपमान : केजरीवाल

► केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर बोला तीखा हमला

नई दिल्ली, 6 मार्च. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा परिसर से जुड़े ऐतिहासिक मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है।

केजरीवाल दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि अंग्रेजों के समय बनी दिल्ली विधानसभा के एक हिस्से में स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी।

केजरीवाल ने कहा कि वर्ष 2022 में इस तथ्य को सामने



लाया गया था ताकि लोगों को इतिहास की जानकारी मिल सके, लेकिन अब भाजपा सरकार इसे फांसीघर के बजाय टिफिन रूम बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया और कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है।

आत्मनिर्भरता ही हर स्थिति से निपटने का मूलमंत्र

► हमारी आत्मनिर्भरता विजन की एक प्रमुख धुरी : राजनाथ

नई दिल्ली 06 मार्च. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा है कि अनिश्चितताओं के इस दौर में आत्मनिर्भरता ही प्रासंगिक और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का एकमात्र मार्ग है।

सिंह ने शुक्रवार को कोलकाता में रक्षा एवं समुद्री संवाद सागर संकल्प-भारत का समुद्री गौरव का उद्घाटन करते हुए कहा, रक्षा क्षेत्र में आज अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हमारी सरकार का शुरु से यह मानना रहा है कि इस अनिश्चितता के दौर में आपूर्ति



श्रृंखला में बाधा से बचने का एक मात्र उपाय है 'आत्मनिर्भरता' और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम हमारी आत्मनिर्भरता के विजन की एक प्रमुख धुरी है। इस कार्यक्रम का आयोजन गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और एक निजी मीडिया संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

चारधाम यात्रा के लिए

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

नई दिल्ली, 06 मार्च. चारधाम यात्रा 2026 के लिए श्रद्धालुओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुक्रवार सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। इस बार भी यात्रा पर जाने से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य किया है, जिससे यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सके. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, चारधाम के कपाट अप्रैल में खुलने वाले हैं. सबसे पहले 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे. इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे.

अमित शाह ने ओडिशा में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन आज



► सीएम मोहन चरण माझी ने भीय स्वागत किया, 69 परियोजनाओं का उद्घाटन

नई दिल्ली, 06 मार्च. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे, जहां उनका मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भव्य स्वागत किया। इस दौरे का

हम बंटे हैं, इसलिए आक्रमण हो रहे हैं : भागवत

► जैसलमेर में जैन चादर महोत्सव में समाज को एकजुट करने का संदेश

जैसलमेर, 06 मार्च. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने जैसलमेर में जैन समाज के चादर महोत्सव कार्यक्रम में कहा कि समाज में आक्रमण और कलह इसलिए होते हैं क्योंकि हम बंटे हुए हैं.

भागवत ने सभी को भेदभाव और स्वार्थ को त्यागकर एकजुट होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम पंथ-संप्रदाय से ऊपर उठकर संस्कृति, देश और समाज के नाते एक हैं। भागवत ने अपने संबोधन में सद्भावना की शुरुआत की अपील की और कहा कि



प्रत्येक मित्र और परिवार हमारे समाज का हिस्सा हैं। कार्यक्रम में भागवत ने पार्श्वनाथ जैन मंदिर में दर्शन-पूजन किए और दादा गुरुदेव की पावन चादर का अवलोकन किया। उन्होंने डॉ. विद्युत प्रभा द्वारा लिखित पुस्तक 'दादा गुरुदेव' का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में जैन समुदाय के लिए स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए गए.

समझौतावादी नीतियों के कारण कमजोर हुई विदेश नीति : खरगे-राहुल

नई दिल्ली, 06 मार्च. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अमेरिकी दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत ने अपने फैसले हमेशा खुद लिए हैं.

लेकिन इधर जिस तरह से अमेरिका के इशारों पर काम हो रहा है उससे लगता है कि हम अपनी कूटनीतिक की गौरवशाली परंपरा को खो रहे हैं।

श्री खरगे ने कहा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय संप्रभुता गंभीर खतरे में है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एपस्टीन फाइल्स और अडानी केस को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है।

यदि हम एकजुट रहेंगे और अपने स्वार्थों को छोड़ेंगे तो समाज मजबूत होगा और भारत विश्वगुरु बन सकता है। जैसलमेर, राजस्थान- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने जैसलमेर के देदासर मेला गार्डन में आयोजित तीन दिवसीय जैन चादर महोत्सव में संबोधन देते हुए समाज में एकता और सहयोग का संदेश दिया। भागवत ने कहा कि आक्रमण और कलह इसलिए होते हैं क्योंकि हम बंटे हुए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पंथ-संप्रदाय से ऊपर उठकर संस्कृति और देश के आधार पर एकजुट हों।



रूस से तेल खरीदने की अनुमति देने की अमेरिकी घोषणा, जो कि 30 दिनों की छूट है, स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मोदी सरकार लगातार कूटनीतिक स्वतंत्रता खो रही है। इस तरह की भाषा प्रतिबंधित देशों के लिए इस्तेमाल की जाती है, न कि भारत के लिए, जो वैश्विक व्यवस्था में एक जिम्मेदार और समान भागीदार रहा है.

विकसित देशों के विद्यार्थी आर्यंगे भारत : गोयल

► अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिये आकर्षित

नई दिल्ली, 06 मार्च. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत भविष्य में अपने शिक्षा संस्थानों में सुविधाएं बढ़ा कर तथा शिक्षण-प्रशिक्षण की आधुनिक प्रौद्योगिकी अपना कर अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिये आकर्षित कर सकता है।

गोयल ने कहा कि नयी शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में परिसर स्थापित करने की छूट मिली है और दूसरे देशों के साथ विद्यार्थियों के आने जाने के सिलसिला बढ़ रहा है। वाणिज्य मंत्री यहां विकसित भारत 2047 के लिए उच्च शिक्षा के



अंतर्राष्ट्रीयकरण की नयी कल्पना विषय पर कुलपतियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इसका आयोजन वाणिज्य मंत्रालय के संस्थान भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) ने किया था। गोयल ने कहा कि 2047 तक भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र में बदलने के सपने को पूरा करने के लिये शिक्षा जगत, सरकार और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाना होगा.

10 लाख युवाओं को एआई प्रशिक्षण, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा

लखनऊ, 06 मार्च. उत्तर प्रदेश- उत्तर प्रदेश सरकार स्टार्टअप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित रिकलिंग के माध्यम से प्रदेश में नवाचार और युवा उद्यमिता को नई गति दे रही है.

योगी सरकार की स्टार्टअप नीति और एआई प्रज्ञा प्रोग्राम का लक्ष्य करीब 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें डिजिटल और तकनीकी रोजगार के अवसर प्रदान करना है। प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, नोएडा और वाराणसी जैसे शहरों में स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एसटीपीआई की लगभग 400 यूनिट्स सक्रिय हैं। इसके साथ ही 100 से अधिक स्टार्टअप



इन्क्यूबेटर विकसित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से युवाओं को उनके नवाचार और तकनीकी विचारों को व्यवसाय में बदलने के लिए मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में देश में लगभग 65व हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बन रहा है.

9 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में नई नियुक्तियां

► राज्यपालों में बड़ा फेरबदल

नई दिल्ली, 06 मार्च. केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्तियों में बदलाव किया है.

इस बदलाव के तहत हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, नागालैंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल समेत कई राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि दिल्ली और लद्दाख जैसे केंद्रशासित प्रदेशों में भी उपराज्यपाल बदले गए हैं। कविंदर गुप्ता को लद्दाख से स्थानांतरित कर हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है.



जिष्णु देव वर्मा



तरनजीत सिंह सिंधू

दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह सिंधू को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बिहार में लैफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल में आर.एन. रवि को राज्यपाल बनाया गया है, जबकि तेलंगाना में शिव प्रताप शुक्ला को नई जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र में जिष्णु देव वर्मा को राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि नागालैंड में नंद किशोर यादव को राज्यपाल बनाया गया है। इसी क्रम में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। सरकार के अनुसार, यह फेरबदल प्रशासनिक संतुलन और विभिन्न राज्यों में शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है.